



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44]  
No. 44]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 1991/माघ 9, 1912  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 1991/MAGHA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कार्मिक, लोक शिक्षा और पेंशन संचालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1991

सा. का. नि. 52(अ):—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) के खण्ड-35 के उपखण्ड (2) की धारा (ड.) के साथ पठित उप खण्ड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1989 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1991 है।

(2) ये नियम पहली नवम्बर, 1989 से प्रभावी होंगे।

2. आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1989

(जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में नियम 3 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक सन्निधापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता या सदस्य के रूप में नियुक्ति की स्थिति में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है या जो पेंशन और या उपदान, अभिव्यक्ति भविष्य निधि में नियोजक के अभिव्यक्ति के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेंशन अथवा सेवा उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिव्यक्ति भविष्य निधि में नियोजक के अभिव्यक्ति या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हो, की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवा निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन कम नहीं की जाएगी।”

3. उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (1) की तरा (i) में “या उसका कोई भाग” ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे

4. उक्त नियमों के नियम 8 में उप नियम (2) के "या उसका कोई भाग" विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"15क, उक्त नियमों के नियम 4 से 15 तक में किसी बात के होते हुए भी आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा शर्तें तथा उन्हें उपलब्ध अन्य परि-लब्धियां नहीं होंगी जो कि उक्त न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उक्त न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1956 में उक्त न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों को अनुसूचित है।"

[संख्या ए-11019/80/90-ए. टी.]

एम. एम. साहारियार, डेस्क अधिकारी (ए.टी.)

टिप्पणी:—मुख्य नियम सरकारी राजपत्र में ता. का. नि. संख्या 930(ई) दिनांक 26-10-1989 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

#### व्याख्यात्मक भाषण

केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा शर्तें और सेवा की शर्तें) नियमावली 1989 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पिछली तारीख से लागू करने से आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC

### GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 1991

G.S.R. 52(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely:

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1991.

(2) These rules shall come into force w.e.f. the 1st day of November, 1989.

2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules) for

the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted, namely :—

Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him."

3. In rule 6 of the said rules, in clause (i) of sub-rule (1), the words "or a part thereof" shall be omitted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2), the words "or a part thereof" shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman and Vice-Chairman of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956."

[No. A-11019/80/90-AT]

S. M. SAHARIAR, Desk Officer (AT)

Note :—The principal rules were published vide GSR No. 930(E) dated the 26th October, 1989 in the Official Gazette.

### EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government had decided to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman or Member of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given affect retrospectively.